डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 22 ● भोपाल ● 16-30 अप्रैल, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

इस वर्ष से तेंदूपत्ता संग्राहकों को तुड़ाई की दर 2000 रुपये मिलेगी - श्री चौहान

सीहोर जिले के सालारोड गाँव में गोंड आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के सालारोड गाँव में गोंड आदिवासी सम्मेलन में बताया कि गोंडी भाषा को तीसरी भाषा दिलाने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जायेगा। भोपाल में रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को किले में पूजा-अर्चना के लिये सहजता से आने-जाने की व्यवस्था के लिये वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पूज्य बड़ा महादेव के पूजा-स्थलों को विकसित किया जाये।

चना बिक्री पर किसानों को मिलेगी 100 रु. अतिरिक्त राशि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष किसानों से चने की खरीदी 4400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जायेगी। खरीदी के बाद कृषकों के खातों में 100 रुपये अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की जायेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों के खातों में 200 रुपये 10 अप्रैल को और इस साल गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों के खातों में 265 रुपये 10 जून को डाले जायेंगे।

श्री चौहान ने बताया कि तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिये इस वर्ष से तेंदूपत्ता तुड़ाई की दर 1200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक महिला श्रमिकों को चरण-पादुका और पानी को ठण्डा रखने वाली कुप्पी के साथ साड़ी भी दी जायेगी। श्री चौहान ने आदिवासी समाज के युवाओं से राज्य शासन की स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ लेने का आव्हान करते हुए बताया कि बैंक लोन की गारंटी राज्य सरकार देगी। उन्होंने आदिवासी समाज से आग्रह किया कि बच्चों को पढ़ायें-लिखायें। बच्चों की उच्च शिक्षा स्तर तक की पढ़ाई के खर्चे की चिंता न करें, पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से योजना में पंजीयन कराने का अनुरोध करते हुए बताया कि पंजीबद्ध श्रमिकों को राज्य शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम सालारोड में बड़ा महादेव की आरती की। श्री चौहान ग्राम आम्बाकदीम में सद्गुरु कबीर पुराण तथा ज्ञान यज्ञ और ग्राम वासुदेव में श्री रामानंद आश्रम में यज्ञ के समापन समारोह में भी शामिल हुए। श्री चौहान ने दोनों ग्राम में जन-संवाद कार्यक्रमों में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

श्री चौहान ने सालारोड के सम्मेलन में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, अपेक्स बैंक प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद शर्मा, वेयर-हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

कड़कनाथ मुर्गा अब ऑनलाइन उपलब्ध

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कड़कनाथ एप का लोकार्पण किया

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने निवास कार्यालय पर मध्यप्रदेश कड़कनाथ एप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेनु पंत, अधिकारी और नागरिक मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। सहकारिता से अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों का गठन कर रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इसी कड़ी में कड़कनाथ मुर्गा-पालन और विक्रय से जुड़ी सहकारी समितियों के लिये मध्यप्रदेश कड़कनाथ मोबाइल एप तैयार कर शुरू किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से व्यक्तियों को स्थानीय परिवेश और उपलब्धताओं को ध्यान में रख उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। व्यक्तियों को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिये जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन और पूँजी की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उपभोक्ता और व्यापारी एप के माध्यम से समितियों तक पहुँच सकते हैं।

(शेष पृष्ठ २ पर)

चना, मसूर, सरसों खरीदी केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर खरीदी केन्द्रों की आवश्यकता का चिन्हांकन कर खरीदी केन्द्रों का निर्धारण किया जाये। श्री चौहान मंत्रालय में रबी–2018 की फसल उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

चना, मसूर, सरसों उपार्जन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान चना, मसूर और सरसों की गुणवत्तापूर्ण फसलें खरीदी केन्द्रों पर लायें। इस संबंध में उनको सूचित और शिक्षित किया जाये। फसलों की उत्पादकता का निर्धारण स्थानीय और व्यवहारिक वास्तविकताओं के अनुसार किया जाये ताकि किसानों की उत्पादित फसल की खरीदी हो सकें। कार्य की गहन निगरानी भी की जाये ताकि व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं की जा सकें। बताया गया कि चना, मसूर, सरसों के 14 लाख 1 हजार 481 किसानों ने पंजीयन करवाया है। चना, मसूर, सरसों की उपार्जन अवधि 10 अप्रैल से 31 मई 2018 है। इस अवधि में सभी संभागों में उपार्जन कार्य होगा।

गेहूँ उपार्जन

श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन कार्य की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि बारदानों की आवश्यकता के अग्रिम आकलन के आधार पर बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उपार्जन व्यवस्था में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो। बताया गया कि गेहूँ उपार्जन के लिए प्रदेश में 2,978 केन्द्रों का गठन किया गया है। कुल 15 लाख 35 हजार 962 कृषकों का पंजीयन किया गया है। खरीदी के संबंध में अभी तक 3 लाख 9 हजार 943 कृषकों को एस.एम.एस. से सूचना दी गई है। इनमें से 1 लाख 36 हजार 575 कृषकों से 6 लाख 52 हजार 60 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो गई है। अभी तक 801 करोड़ 12 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है।

फसलों के नुकसान पर अब न्यूनतम 5 हजार और अधिकतम 1.20 लाख मिलेंगे

भोपाल। राज्य शासन द्वारा फरवरी 2018 में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान तथा भविष्य में होने वाली इसी प्रकार की फसलों के नुकसान पर दिये जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–6 क्रमांक 4 में संशोधन कर दिया गया है।

आदेशानुसार कम मूल्य की फसल की क्षति होने पर अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी। पहले यह राशि 2 हजार रूपये थी।

इसी तरह, फसल हानि के लिये अथवा फलदार पेड़, उन पर लगे संतरा, नीबू, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों और पान बरेजा आदि की हानि होने पर किसी भी खातेदार को आर्थिक अनुदान सहायता अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपये तक दी जा सकेगी। पहले अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा 60 हजार रूपये थी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

कड़कनाथ मुर्गा अब ऑनलाइन उपलब्ध

एप द्वारा समितियों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो उन्हें आधुनिक बाजार की सुविधा देगा। एप में उपलब्ध मेन्यु में सीधे क्लिक करने पर समिति का ई–मेल, फोन और उत्पादन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माँग और पूछताछ का ऑप्शन भी दिया गया है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से सीधे संस्था को ई–मेल करने की सुविधा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा अन्य प्रजातियों के मुर्गों से बेहतर होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और फेट की मात्रा न के बराबर पायी जाती है। उन्होंने बताया कि विटामिन–बी–1, बी–2, बी–6, बी–12, सी, ई, नियासिन, केल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। यह अन्य मुर्गों की तुलना में लाभकारी है। इसका रक्त, हड्डियाँ और सम्पूर्ण शरीर काला होता है। यह दुनिया में केवल मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाता है।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि झाबुआ, अलीराजपुर और देवास जिले में कड़कनाथ मुर्गा–पालन की 21 सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है। इनमें 430 सदस्य हैं। एप में इनकी पूरी जानकारी है। चार समितियों द्वारा व्यवसाय शुरू कर दिया गया है। शेष समितियाँ व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। कड़कनाथ एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन समितियों के पास उपलब्ध कड़कनाथ मुर्गा खरीदने के लिये ऑनलाइन डिमाण्ड कर सकता है। भविष्य में ऑनलाइन आर्डर के साथ होम डिलीवरीकी भी सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

पैक्स के डिफाल्टर किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का लाभ

भोपाल। प्रदेश के प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिये ऋण समाधान योजना लागू की गई है। किसान 15 जून 2018 तक अपने बकाया ऋण के मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

योजना का लाभ लेने के लिये कृषक द्वारा बकाया मूलधन की 50 प्रतिशत राशि को 15 जून 2018 तक एक मुश्त अथवा किश्तों में जमा कराना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकाई जायेगी, उसी दिन कृषक को इस राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन नगद ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा। साथ ही, उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जायेगी। कृषक को नवीन ऋण मान के अन्तर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा।

योजना में सम्मिलित होने वाले कृषकों को ख़रीफ 2018 सीजन में नगद ऋण की मात्रा आधे मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी। ऋण का शेष भाग वस्तु ऋण के रूप में होगा। आगामी रबी सीजन 2018–19 और इसके बाद आने वाले कृषि मौसमों में यह बंधन लागू नहीं रहेगा और नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात नियमित श्रेणी के कृषकों की भांति रहेगा।

योजना की परिधि में गबन, धोखाधड़ी से संबंधित ऋण प्रकरण शामिल नहीं होंगे। जिला स्तर पर योजना का समयावधि में क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व जिले के उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का होगा। योजना में अपलेखित ब्याज की राशि का दायित्व भार 80 प्रतिशत राज्य शासन और 20 प्रतिशत संबंधित पैक्स संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

कड़कनाथ मुर्गीपालन संरक्षण प्रशिक्षण में सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को मुर्गीपालन हेतु प्रोत्साहित किया

आयुक्त सहकारिता रेनु पंत ने कड़कनाथ एप के बारे में भी बताया

झाबुआ। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाए म. प्र. भोपाल रेनु पंत ने झाबुआ के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कड़कनाथ मुर्गीपालन संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन किया।

उन्होंने बताया कि कड़कनाथ मुर्गे के पालन और खरीद–फरोख्त के कारोबार से जुडी सहकारी समितियों के लिए म.प्र. कड़कनाथ मोबाइल एप तैयार किया है। एप समितियों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें आधुनिक बाजार मिलेगा। एप में झाबुआ, अलीराजपुर और देवास जिले की कड़कनाथ मुर्गा पालन के लिए काम कर रही चार सहकारी समितियों सहित 20 से ज्यादा संस्थाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने समितियों के सदस्यों को कड़कनाथ चूजों के विकास एवं मार्केटिंग के गुर सिखाए।

कलेक्टर आशीष सक्सेना, बैंक अध्यक्ष गौरसिंह वसुनिया, डीएफओ अनिल शुक्ला, जिपं सीईओ जमुना भिडे, संयुक्त आयुक्त सहकारिता अभय खरे, उपायुक्त सहकारिता भारती शेखावत, बैंक सीईओ पीएन यादव तथा केएल राठौर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा आयुक्त सहकारिता का स्वागत किया गया। स्वागत भाषण में भारती शेखावत द्वारा मुर्गीपालन सहकारी समितियों संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया। बैंक अध्यक्ष गौरसिंह वसुनिया ने कहा कि वर्तमान में 17 सहकारी समितियों का गठन झाबुआ जिले में हो चुका है, जिसमे से दो समितियों को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दोनों समितियां अच्छा कार्य कर रही है। कड़कनाथ मोबाइल एप भी लांच किया गया है। मोबाइल एप पर समस्त जानकारी अपलोड करना होगी, ताकि आपकी समिति की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। इससे आपका सशक्तिकरण होगा एवं आपको अच्छे दाम की प्राप्ति हो सकेंगे।

आशीष कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था के अध्यक्ष विनोद मेडा द्वारा कडकनाथ उत्पादन की जानकारी दी गई एवं वर्तमान में 540 चूजे–मुर्ग की पैदावार हो चुकी है। चूजे उत्पादन की मशीन केरल राज्य से लाई जाकर लगभग 825 वर्गफीट में शेड बनाया जाकर, अलग–अलग लाट में रखा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर, प्रेम द्विवेदी उपायुक्त सहकारिता भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएन यादव, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डाबर एवं डॉ. अमरसिंह दिवाकर द्वारा भी प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई। नितिन जौहरी सिस्टम एक्जीक्यूटिव द्वारा मोबाइल एप डेमोस्टेशन दिया गया। प्रशिक्षण का संचालन राज्य सहकारी संघ के निरंजन कुमार कसारा द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग जिला झाबुआ–अलीराजपुर एवं बैंक के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

झाबुआ का प्रसिद्व कड़कनाथ मुर्गा एप पर लांच होते ही 24 घंटे के भीतर 17 ऑर्डर आ गए। इसमें दिल्ली से सात, इंदौर और बालाघाट से तीन मुर्गों की मांग आई है। पहला ऑर्डर पेटलावद के विनोद मेढ़ा को मिला है। पहले दिन की मांग को देखते हुए अब होम डिलिवरी की योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए लोन भी दिया जाएगा।

झाबुआ जिले में 17 एवं अलीराजपुर जिले में 6 कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। अब इस समितियों को जिला सहकारी बैंक के जरिये सरकार 3 लाख 80 हजार प्रति समिति लोन देगी जिससे यह समितियां कड़कनाथ पालन हेतु शेड एवं हेचरी का निर्माण कर सकेंगे।

सहकारी समिति के विकास हेतु प्रबंधक समर्पित भाव से कार्य करें

सतना। म.प्र.राज्य सहकारी संघ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सतना में 3 दिवसीय समिति प्रबंधक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 19 से 21 मार्च 2018 तक बैंक सभागार में किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्रवक्ता एस.के. चतुर्वेदी द्वारा प्रबंधकों को लेखा पद्धति, उपनियम एवं सहकारी अधिनियम के बारे में बताया गया। समापन अवसर पर पूर्व अध्यक्ष पं. कमलाकर चतुर्वेदी मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए समिति प्रबंधकों को समर्पण भाव से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में समितियों का अस्तित्व बनाये रखना बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार कर समय पर ऋण की वसूली करें ताकि समितिएवं समिति प्रबंधकों का अस्तित्व बना रहें। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि समितियों को हानि से बचाये एवं लेखा संधारण समय पर करें। बैंक के विशिष्ट अतिथि प्रोफेशनल डायरेक्टर श्री रामेश्वर तिवारी ने समिति प्रबंधकों को वैधानिकता का पालन करते हुए कर्तव्य निर्वहन में प्रशिक्षण का महत्व बताया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ सहकारी कार्यकर्ता एवं बैंक डायरेक्टर विपणन समिति मैहर के अध्यक्ष श्री जर्नादन शुक्ला ने सहकारिता आंदोलन की आवश्यकता पर चिंतन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रबंधक समर्पित भाव से कृषकों की सेवा करना समय की अनिवार्यता है। कृषक सहकारी समितियों का मालिक एवं ग्राहक दोनों हैं। प्रबंधको के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध होने चाहिये जिससे समिति एवं कृषकों दोनों शासकीय योजनाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रायकवार ने अच्छा काम करने की सलाह दी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। आभार प्रदर्शन भूपेन्द्रसिंह के द्वारा किया गया।

चार नई तहसील गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में चार नई तहसील के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। जिला बैतूल में भीमपुर और प्रभातपट्टन, उमरिया में बिलासपुर और सागर में जैसीनगर तहसील का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने जानकारी दी है कि तहसील भीमपुर में 54 पटवारी हलके तथा 154 ग्राम, प्रभातपट्टन में 65 पटवारी हलके तथा 120 ग्राम, बिलासपुर में 16 पटवारी हलके और 76 ग्राम तथा जैसीनगर तहसील में 62 पटवारी हलके और 149 ग्राम शामिल होंगे।

मत्स्य महासंघ के श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू

मत्स्य पालन मंत्री की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ काम-काजी समिति की बैठक

भोपाल। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से अब अन्य छात्रवृत्ति के साथ निषादराज छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलेगा। पहले अन्य छात्रवृत्ति पा रहे मछुआरों के ब%चे इस योजना के पात्र नहीं थे। योजना में सामान्य विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये तक और तकनीकी विषयों में 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जाती है। इससे मेधावी छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।

बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री वी.सी.सेमवाल, संचालक मत्स्योद्योग श्री ओ.पी. सक्सेना, प्रबंध संचालक म.प्र. मत्स्य महासंघ श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं श्री विनोद कुमार सिंह, उप कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी.एस. धुर्वे भी मौजूद थे।

मत्स्य महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी लागू कर दी गई है। श्रमिकों को इसका लाभ एक जनवरी 2018 से मिलेगा। इसमें महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर और उस पर महासंघ का अंशदान 12 प्रतिशत, इस प्रकार कुल 24 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। काम-काज समिति ने वर्ष 2017-18 में स्पान, स्टेण्र्ड फ्राई उत्पादन, मत्स्य बीज संचय, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य कल्याण कार्य-योजनाओं की प्रगति, हलाली जलाशय से तिलोपिया मछली की छटाई, महाशीर मत्स्यबीज उत्पादन आदि योजनाओं की समीक्षा भी की।

सांची दूध के विक्रय एवं विपणन के लिए मोबाईल एप शुरू

डेयरी उद्योग आधुनिकीकरण पर कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल। डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण एवं नवीन अवधारणा पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी ने किया। इस अवसर पर कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय एवं विपणन के लिए निर्मित साफ्टवेयर तथा मोबाईल एप का अनावरण किया गया।

कार्यशाला में दुग्ध सहकारी समिति में आटोमेटिक दुग्ध परीक्षण, पशुओं के तत्काल इलाज के लिए इनॉफ साफ्टवेयर के माध्यम से 1962 डायल सेवा, डेयरी उद्योग में फोटो तकनीक के माध्यम से दुग्ध संचालन, नवीन दुग्ध पदार्थ, दुग्ध सहकारी समितियों की जीआईएस मेपिंग के माध्यम से प्रत्येक दुग्ध समिति की लोकेशन एवं विस्तृत जानकारी का एकीकरण तथा 1 और 2 श्रेणी के दूध के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुग्ध मशीन निर्माता कंपनियों द्वारा डेयरी उद्योग में नवीन तकनीक की मशीनों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से ऐसिप्टक मिल्क उत्पादन, दुग्ध शीतलीकरण की नवीन मशीनें, आटोमेटिक दुग्ध जाँच एवं नियंत्रण, डेयरी यांत्रिकी में नवीन अवधारणाएँ, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नवीन तकनीक, दूध में मिलावट के परीक्षण के लिए नवीन तकनीक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर आयुक्त, सहकारिता श्रीमती रेनु पंत, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ डॉ.अरूणा गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित श्री जितेन्द्र सिंह राजे, संचालक, पशुपालन डॉ. आर.के. रोकडे तथा प्रबंध संचालक, कुक्कट विकास निगम डॉ. एच.वी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।

साँची दूध की गुणवत्ता है एफएसएसएआई के मानक अनुसार

भोपाल। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र राजे ने बताया कि संघ द्वारा एफएसएसएआई के फैट/एनएनएफ के मानक अनुसार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह दूध विभिन्न आयु वर्गों के लिये उपयोगी है। दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित गोल्ड दूध पैकेट में 6 प्रतिशत फैट, 9 प्रतिशत एसएनएफ, शक्ति में 4.5 फैट और 8.5 एसएनएफ, चाह में 4.5 फैट, 9 एसएनएफ, ताजा में 3 फैट, 8.5 एसएनएफ, स्मार्ट में 1.5 फैट और 9 एसएनएफ तथा लाइट दूध पैकेट में 0.1 प्रतिशत फैट और 8.7 प्रतिशत एसएनएफ होता है।

दुग्ध संघ द्वारा ग्रामीण स्तर की दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध को संकलित कर संयंत्र में पाश्चुराइज किया जाता है। विभिन्न प्रकार का दूध मानक स्तर के आधार पर हाईजेनिक स्थिति में तैयार और पैक कर उपभोक्ताओं को कोल्डचेन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

दुग्ध संयंत्र में ग्राम-स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों से प्राप्त दूध को बाजार की माँग के अनुसार विभिन्न लॉट में मानक-स्तर पर निर्मित कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। जहाँ तक दूध का पतला और कम मलाई का होने का प्रश्न है, संघ को दूध उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सभी 6 प्रकार के दूध मानक-स्तर पर ही प्रदाय किये जा रहे हैं। किसी भी उपभोक्ता की संघ के हेल्पलाइन नम्बर पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संघ की गुणवत्ता शाखा द्वारा त्वरित निराकरण किया जाता है।

भोपाल दुग्ध संघ किसी भी प्रायवेट फर्म से दुग्ध चूर्ण खरीद नहीं रहा है। वर्तमान में अत्यधिक दुग्ध उत्पादन होने की स्थिति में प्रायवेट संयंत्रों से भी दुग्ध चूर्ण बनवाया जा रहा है। प्रायवेट संयंत्रों में निर्मित हो रहे दूध पावडर की गुणवत्ता की जाँच संघ की गुणवत्ता शाखा द्वारा निरीक्षण और परीक्षण के माध्यम से निरंतर की जाती है।

रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सेमीनार का आयोजन

शिवपुरी। जिला शिवपुरी में म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के तत्वावधान में दिनांक 6.4.2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी व जिला सहकारी संघ मर्यादित, शिवपुरी के सहयोग से जिले के किसानों हेतु रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सेमीनार का आयोजन सम्पन्न हुआ। सेमीनार में कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिक डा. एम.के. भार्गव ने संतुलित पोषक तत्व एवं रासायनिक उर्वरकों तथा खरीफ कार्य योजना हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिससे कृषको की आय दुगुनी हो सके एवं कृषकों के प्रश्न के उत्तर दिये। कृषि विभाग के सहायक संचालक श्री जी.के. श्रीवास्तव ने मिट्टी परीक्षण कृषि व पशुपालन पर जानकारी दी तथा इफको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आर.के. महोलिया द्वारा मिट्टी नमूना, हरी खाद उपयोग, जैव उर्वरक उपयोग अन्य जानकारी दी गई और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी के महाप्रबंधक श्री ए.एस. कुशवाह द्वारा किसानों के लिये चलाई जा रही कृषि संबंधी शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के व्याख्याता श्री गणेश मांझी ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की गतिविधियों व सहकारिता की जानकारी देते हुये मंच का संचालन किया गया तथा प्रशिक्षक श्री कालका प्रसाद श्रीवास्तव ने कृषकों को जैविक खाद एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर सुझाव दिये तथा जिला सहकारी संघ मर्यादित, शिवपुरी के प्रभारी प्रबंधक श्री आर.एन. गुप्ता द्वारा उपस्थित कृषक सदस्य एवं अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया गया।

किसानों को मेहनत का पूरा लाभ और सम्मान मिलेगा-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मुरैना में की किसान सम्मान यात्रा की अगवानी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले में किसान सम्मान यात्रा के अंतर्गत आयोजित किसान सभा में कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ और सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण पर लगने वाली फीस माफ करने की घोषणा की। श्री चौहान ने इस मौके पर जिले के किसानों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही प्रदेश को पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ही खुश नहीं होगा, तो प्रदेश कैसे सुखी हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता 40 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता 80 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार कई योजनाएँ संचालित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब फसल का मूल्य निर्धारण करने के लिए प्रदेश स्तर पर समिति गठित की गई है। फसलों के निर्यात के लिए कृषि उत्पाद निर्यात एजेंसी बनाई जा रही है।

श्री चौहान ने कहा कि किसान के घाटे की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। किसी भी आपदा से किसान की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है, तो उसे प्रति हेक्टेयर 30 हजार की राहत राशि दी जाएगी। असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में ढाई एकड़ से कम भूमि वाले किसान को भी शामिल किया गया है। चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार किसानों के साथ है। चंबल नहर का पानी पूरे चंबल रीजन में पहुँचाया जा रहा है। चंबल के बीहड़ों को गुलजार करने के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ चंबल रीजन में आर्मी की भर्ती के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान यात्रा का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देना तथा खेती को लाभ का धंधा बनाना है। यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और किसानों का सम्मान करेगी।

किसानों को मिलेंगे पूर्व वर्ष के 200 रूपए : मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को भी 200 रूपए प्रति क्विंटल के मान से उनके खाते में राशि प्रदान की जायेगी। जानकारी एसएमएस के माध्यम से किसानों को दी जायेगी। किसानों द्वारा खाता नम्बर में कोई परिवर्तन किया गया है, तो वे इसमें संशोधन करा सकते हैं। राशि किसानों को 16 अप्रैल को प्रदान की जायेगी।

किसान समृद्धि योजना में मिलेंगे 265 रूपए : श्री चौहान ने कहा कि किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत 265 रूपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कोई कृषक समर्थन मूल्य पर गेंहू की फसल अगर मंडी में बेचता है, तब भी उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि अब 27 अप्रैल : मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ वर्ष 2017 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा जीरो प्रतिशत ब्याज पर वितरित अल्पावधि फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य से जुड़े युवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगायें। इसके लिए सरकार 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपये तक लोन दिलवाएगी। लोन की गारंटी भी सरकार देगी। योजना में 15 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा और 7 वर्ष तक ब्याज सरकार भरेगी।

केन्द्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2003 के पहले गेंहू उत्पादन में लोग पंजाब और हरियाणा का नाम लिया करते थे। आज मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में देश में नम्बर वन प्रदेश बन गया है। सांसद श्री नन्द कुमार चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया।

इस अवसर पर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती माया सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, महापौर श्री अशोक अर्गल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हर्षाना, सांसद श्री भागीरथ प्रसाद, विधायक श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, श्री भारत सिंह कुशवाह, श्री सूवेदार सिंह रजौधा, श्री दुर्गालाल विजय, श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, पूर्व मंत्री श्री मुंशीलाल, संगठन मंत्री श्री शैलेन्द्र वरूआ, प्रदेश महामंत्री श्री बी.डी. शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष भरत, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में कृषक एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

किसान सम्मान यात्रा की अगवानी : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की सीमा आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुरैना के समीप किसान सम्मान यात्रा की अगवानी की। तत्पश्चात रथ में किसान सम्मेलन में पहुँचे। यात्रा मथुरा के बलदाऊ मंदिर से चलकर मुरैना पहुँची थी।

रिहा हुए बंदियों को अंत्योदय योजना में मिलेगा रोजगार - श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जेल से रिहा होने वाले अच्छे चरित्र और रोजगार के इच्छुक बंदियों को सहकारिता विभाग की अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन से ऐसे बंदियों की सूची प्राप्त कर इनकी समितियाँ गठित करवाई जा रही हैं। अंत्योदय योजना के तहत यह नवाचारी पहल की गई है। श्री सारंग भोपाल की केन्द्रीय जेल में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

श्री सारंग ने कहा कि व्यक्ति सजा पूरी करने के बाद वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिये रोजगार का संकट उत्पन्न न हो। इसके लिये ही सहकारिता विभाग ने अंत्योदय योजना में समितियों के माध्यम से रिहा हुए बंदियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की पहल की है। समितियों के लिये बैंकों से पूँजी की व्यवस्था की गई है।

राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्र और समाज के लिए जीना ही जीवन की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि बंदी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का संकल्प लें।

पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने किया भोपाल दुग्ध संघ का आकस्मिक निरीक्षण

घी, दूध और दुग्ध आपूर्ति टैंकरों की जाँच की

भोपाल। पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने भोपाल दुग्ध संघ का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्री आर्य ने दूध आपूर्ति से लेकर दुग्ध वाहन में लोडिंग तक सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारी ली। श्री आर्य द्वारा पिछले दिनों पकड़े गये टैंकर के बारे में पूछताछ करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह राजे ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने जीपीएस में उस टैंकर का रुकना पाया था, जिसके कारण कार्यवाही कर उसे ब्लेक-लिस्टेड कर दिया गया है। मंत्री श्री आर्य ने दुग्ध वाहन के अंदर जाकर चेकिंग की। उन्होंने घी, पेड़ा, मठ्ठा प्लांट, लैब में दूध, घी आदि की टेस्टिंग, एग्मार्क लैब और मॉनीटरिंग-कक्ष भी देखा।

इस वर्ष गर्मियों में नहीं होगी दूध की कमी : मंत्री श्री आर्य ने गर्मियों में उपभोक्ताओं को दूध की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिये। मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती अरुणा गुप्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में प्रदेश में दुग्ध संकलन केन्द्रों की बढ़ोत्तरी से इस वर्ष गर्मी में कमी की आशंका नहीं है। नये केन्द्रों से पिछले साल एक लाख लीटर दूध मिला था। इस वर्ष तीन लाख लीटर

मिलने की उम्मीद है।

साँची महाकाल मंदिर को रोज 3 टन घी की आपूर्ति : मंत्री श्री आर्य को बताया गया कि फेडरेशन द्वारा महाकाल मंदिर को रोज 3 हजार किलो घी की आपूर्ति की जाती है। फेडरेशन ने पिछले 6 माह में 2 हजार मीट्रिक टन घी का विक्रय किया है। मंत्री ने लैब में दूध और घी का परीक्षण करवाकर गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने मिल्क पावडर की भी जाँच की। श्री आर्य को बताया गया कि जब दूध का संकलन आपूर्ति से अधिक हो जाता है, तो उसे पावडर के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है।

बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ शुरू : मंत्री श्री आर्य को बताया गया कि एक अप्रैल, 2018 से बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ ने काम शुरू कर दिया है। महिला स्व-सहायता समूह इसमें सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वहाँ उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध और दूध के उत्पाद मिलने लगे हैं। सेंधवा में भी जल्दी ही नया प्लांट काम करना शुरू कर देगा। वहाँ पशु आहार प्लांट भी लगाया जा रहा है। इनसे स्थानीय स्तर पर दो-ढाई हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने के लिये जिलों में समिति गठित

26 मई तक कृषि उपज मंडी में गेहूँ बेचने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

भोपाल। प्रदेश में प्रमुख कृषि फसलें गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की उत्पादकता बढ़ाने और फेयर एवरेज क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। योजना में खरीफ 2016 में धान और रबी 2016-17 में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई-उपार्जित मात्रा पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसान के बैंक खाते मे जमा करवायी जाएगी। इसके साथ ही रबी 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले किसानों के खाते में 265 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जमा करवायी जायेगी। यह राशि इस वर्ष 15 मार्च से 26 मई तक गेहूँ बेचने वाले किसानों के खाते में जमा करवायी जाएगी। इसके अलावा रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जित कराने वाले किसानों को 100 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में जमा करवायी जायेगी।

योजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश दिये हैं। क्रियान्वयन समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम और जिला प्रबंधक मार्कफेड को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति में सदस्य सचिव उप-संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास को बनाया गया है।

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि कृषि उत्पाद मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों ही स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिया जायेगा। रबी 2016-17 में गेहूँ तथा खरीफ 2017 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ई-उपार्जित कराये गये समस्त किसानवार डाटाबेस का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बाद जानकारी संचालक किसान-कल्याण को उपलब्ध करवायी जायेगी। सत्यापित डाटाबेस के आधार पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जिलों को उपलब्ध करवायी जायेगी।

कलेक्टर की अध्यक्षता वाला समिति किसानों के डाटाबेस का परिक्षण कर पुष्टि करेगी। इसके बाद किसानों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करवायी जायेगी। इसकी सूचना किसानों को मोबाईल पर एसएमएस से दी जायेगी। लाभान्वित किसानों के सत्यापित बैंक खाते में गड़बड़ी हो जाने पर अथवा किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय जाँच के बाद 15 दिन के भीतर किसान के नवीन प्रमाणीकृत बैंक खाते में योजना की राशि जमा करवायी जायेगी।

मुख्यमंत्री समृद्धि योजना में किसानों की संतुष्टि के आंकलन के लिये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आंकलन सर्वेक्षण भी करवाया जायेगा।

नर्मदा घाटी में सिंचाई विस्तार की अभूतपूर्व प्रगति

चौदह बरस में सिंचाई रकबा छह हजार से हुआ छह लाख हेक्टेयर

भोपाल। अथाह जल राशि से भरी नर्मदा का जल आज से चौदह वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी के केवल 6,100 हेक्टेयर क्षेत्र तक ही पहुँच पाता था। आज नर्मदा, नर्मदा घाटी में 6 लाख हेक्टेयर रकबे को सींच रही है। सिंचाई विस्तार की यह उल्लेखनीय प्रगति लीक से हटकर किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है। अनुमान है कि आगामी पाँच वर्ष में वर्तमान सिंचित रकबे में इतनी ही बढोत्तरी और हो जायेगी।

लीक से हटकर किये जाने वाले प्रयासों का मार्ग मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा और नर्मदा घाटी के प्रति सोच और प्राथमिकता से निकला है। नर्मदा घाटी में सिंचाई के बड़े लक्ष्यों के लिये बड़े बाँध, बड़ी नहरें बनाना ही निश्चित था। इससे जुड़े भू-अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास और मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से सिंचाई विस्तार की गति अपेक्षा अनुसार नही आ पाती थी। नर्मदा के जल को घाटी के गाँव-गाँव और खेत-खेत तक किसी भी तरह ले जाने के मुख्यमंत्री के संकल्प से जो नई राह निकली, उसके अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा के जल को उद्वहन कर गाँव-गाँव तथा खेत-खेत तक ले जाने के नये अभियान में जुटा। इस अभियान की सफलता के लिये आत्म-विश्वास दिया नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ-लिंक योजना ने। केवल 14 माह की अवधि में नर्मदा का जल 400 मीटर ऊपर मालवा-पठार में पहुँचा और यह निश्चित हो गया कि नर्मदा का जल घाटी के हर क्षेत्र तक पहुँचना संभव है।

सिंचाई विस्तार के नये प्रयासों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने 29 उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजनाओं के निर्माण की तैयारी कर ली है। ये योजनायें आगामी 2 से 5 वर्ष के समय में निर्मित हो जायेंगी। इन योजनाओं से 9 लाख 75 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इन नवाचारी योजनाओं से घाटी के इन्दौर, उ%जैन, खरगोन, खण्डवा, अलीराजपुर, सीहोर, देवास, कटनी, शाजापुर, राजगढ, नरसिंहपुर और रायसेन जिले के किसान माइक्रो सिंचाई का लाभ लेने लगेंगे।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

मुख्यमंत्री श्री चौहानऊर्जा विभाग की समीक्षा

भोपाल। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के तहत अब तक प्रदेश में 12 लाख 30 हजार 360 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जाये। विद्युत कंपनियाँ अपने अमले का बेहतर प्रबंधन करें। निचले स्तर पर दक्षता बढ़ायी जाये। विद्युत चोरी को रोकने और वसूली बढ़ाने के लिये काम करें। बैठक में असंगठित मजदूरों के बिजली बिलों की सरल बिल योजना और प्रस्तावित विद्युत बिलों की बकाया भुगतान की समाधान योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। विद्युत बिलों का सरलीकरण करें। विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमिती करण करें।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 450 करोड़ विद्युत यूनिट की आपूर्ति हुई है। मुख्यमंत्री स्थायी

कृषि पम्प योजना में अब तक कुल 2 लाख 77 हजार पम्प कनेक्शन किये गये हैं। इस वर्ष में दिसम्बर माह के अंत तक इस योजना में सवा लाख नये कनेक्शन दिये जायेंगे। सौभाग्य योजना में तीस लाख 14 हजार 439 के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख 20 हजार 360 घरों में कनेक्शन किये गये हैं। प्रदेश के चार जिले नीमच, इंदौर, मंदसौर और आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रस्तावित सरल बिल योजना में असंगठित मजदूरों को फ्लेट रेट से 200 प्रति माह बिजली बिल देय होगा। प्रस्तावित समाधान योजना में सरचार्ज और मूल बकाया राशि का 70 प्रतिशत माफ किया जायेगा, शेष 30 प्रतिशत चार किश्त में भुगतान करना होगा। योजना में एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत माफी और 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये एप विकसित किया गया है। उपभोक्ता केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केसरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक भी उपस्थित थे।

केरल के सहकारिता मंत्री से मिले राज्यमंत्री श्री सारंग

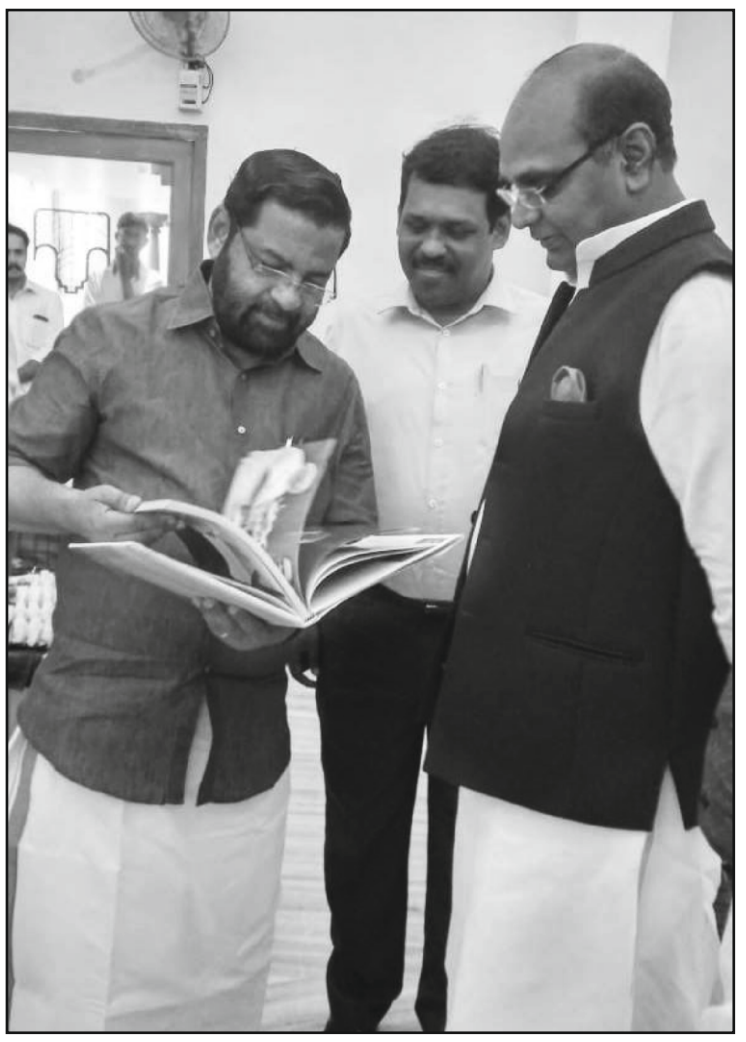

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज तिरुवनंपुरम में केरल के सहकारिता, पर्यटन एवं देवस्थानम् मंत्री श्री के. सुरेन्द्रन से सौजन्य भेंट की। श्री सारंग ने प्रदेश में संचालित सहकारिता से अन्त्योदय योजना और ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नवाचारी प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री श्री सुरेन्द्रन ने केरल राज्य में सहकारी आन्दोलन की गतिविधियों के बारे में बताया।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने श्री सुरेन्द्रन से मिलने के बाद सहकारी पंजीयक डॉ.डी.साजिद बाबू के साथ बैठक की। बैठक में केरल के अतिरिक्त पंजीयक श्री पी. राजेश और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। डॉ. बाबू ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से केरल राज्य की सहकारी साख संस्था, मसाला सहकारी संघ, काजू प्रं-संस्कारण संघ सहित अन्य सहकारी गतिविधियों की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री से पुरस्कृत हुए मध्यप्रदेश के कृषक नरेश पटेल

भोपाल। नरसिंहपुर जिले में विकासखंड चीचली के ग्राम कनवास के प्रगतिशील किसान नरेश पटेल ने वर्ष 2015-16 में एक हेक्टर में 99.80 क्विंटल गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन किया। इस उपलब्धि पर श्री पटेल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरस्कृत किया। कृषक नरेश पटेल ने खेती में नवाचार अपनाया और सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसीफिकेशन-एसडब्ल्यूआई पद्धति से जीडब्ल्यू-366 किस्म के गेहूं की फसल लगाई। इसके लिए उन्होंने कतार से कतार की दूरी 12 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच रखी। गेहूँ के दो-दो दाने लगाये। उन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि विभाग से पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। परिणाम उम्मीद से भी %यादा अ%छा मिला। एक हेक्टर में 99.80 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन मिला।

कृषक नरेश पटेल बताते हैं कि उन्होंने खेत में पहले मूंग की फसल बोई और इसे खेत में ही बखर दिया। इससे खेत की मिट्टी को हरी खाद मिल गई। कुछ समय के बाद गोबर की खाद और वर्मी-कम्पोस्ट का प्रयोग भी किया। एसडब्ल्यूआई पद्धति से गेहूँ की बोवनी की। उनका कहना है कि यदि परम्परागत तरीके से खेती करते, तो कम उत्पादन होता। नवाचार अपनाने से यह फायदा मिला है। एक हेक्टर में लगभग 35 हजार रूपये की लागत आई, जिसमें मजदूरी, ट्रेक्टर, खाद, सिंचाई, बिजली, बोवनी आदि की लागत भी जुड़ी हुई है। उन्हें प्रति एकड़ 50 हजार रूपये का लाभ प्राप्त हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषक नरेश पटेल को पुरस्कृत किया। पुरस्कार में उन्हें दो लाख रूपये की नगद राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पैक्स अल्पावधि फसल ऋण अदायगी की अंतिम तिथि हुई 27 अप्रैल

भोपाल। खरीफ फसल 2016-17 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा वितरित अल्पावधि फसल ऋण की अदायगी किसान किसान अब 27 अप्रैल, 2018 तक कर सकेंगे। पूर्व में योजनान्तर्गत किसानों को 28 मार्च तक ऋण की अदायगी करने की छूट दी गई थी। ऋण अदायगी की समय-सीमा में एक माह की बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों के लिये वर्ष 2016-17 में लागू अल्पावधि फसल योजना को वर्ष 2017-18 में निरंतर रखा गया है। राज्य शासन द्वारा लिये गये इस निर्णय के अनुपालन में अदायगी की तारीख बढ़ाई गई है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।